भारत सरकार

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 3780

मंगलवार, 12 अगस्त, 2025 को उत्तर दिए जाने के लिए

आंध्र प्रदेश के ओडीओपी उत्पादों को बढ़ावा देना

3780. श्री पुट्टा महेश कुमारः
श्री मगुंटा श्रीनिवासुलू रेड्डीः
श्री कृष्ण प्रसाद टेन्नेटीः

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने विगत पांच वर्षों के दौरान आंध्र प्रदेश में एक जिला एक उत्पाद (ओडीओपी) पहल और इसके कार्यान्वयन के संबंध में कोई जिलावार अध्ययन/सर्वेक्षण किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और विगत पांच वर्षों के दौरान आंध्र प्रदेश के प्रत्येक जिले से, विशेषकर एलुरु, प्रकाशम और बापतला लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र जिलों से, ओडीओपी उत्पादों का जिलावार और तिथिवार कुल निर्यात (मात्रा और मूल्य में) कितना है;

(ग) आंध्र प्रदेश में, विशेषकर एलुरु, प्रकाशम और बापतला लोक सभा निर्वाचन क्षेत्रों में ओडीओपी उत्पादों की बिक्री को बढ़ावा देने के लिए प्रस्तावित, विकासाधीन और वर्तमान में कार्यशील अवसंरचना के विकास के सम्बंध में जिलावार ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या सरकार ने आंध्र प्रदेश में अपने ओडीओपी आधारित उत्पादों की बिक्री को बढ़ावा देने के लिए सरकारी कार्यालयों, एमएसएमई और उद्यमियों (विशेषकर युवाओं और महिलाओं) को प्रशिक्षित करने के लिए कोई पहल की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री जितिन प्रसाद)

(क): एक जिला एक उत्पाद (ओडीओपी) कोई स्कीम नहीं है, बल्कि उद्योग संवर्धन एवं आंतरिक व्यापार विभाग (डीपीआईआईटी) की पहल है, जिसके अंतर्गत कोई वित्तीय घटक शामिल नहीं है। अत:, विगत पांच वर्षों में आंध्र प्रदेश में इसके कार्यान्वयन के संबंध में सरकार द्वारा कोई औपचारिक अध्ययन या जिलावार सर्वेक्षण नहीं

किया गया है। राज्य ने आंध्र प्रदेश के 26 जिलों से 99 उत्पादों (23 प्राथमिक, 19 द्वितीयक, 13 तृतीयक और 18 अन्य श्रेणी के उत्पाद) की पहचान की है और राज्य के भीतर ओडीओपी हितधारकों के संवर्धन और सशक्तीकरण के लिए कई कार्यकलाप शुरू किए हैं। आंध्र प्रदेश के 99 ओडीओपी उत्पादों का क्षेत्रवार विभाजन निम्नानुसार है:

उत्पाद श्रेणी	**उत्पादों की संख्या**
कृषि	7
खाद्य प्रसंस्करण	05
हस्तशिल्प	29
हथकरघा	32
विनिर्माण	6
समुद्री	03
अन्य	02
वस्त्र	15
कुल	**99**

राज्य ने कई प्रमुख उपायों के माध्यम से मज़बूत ओडीओपी ईकोसिस्टम तैयार किया है। सभी 99 चिन्हित उत्पादों को आंध्र प्रदेश एमएसएमई एवं उद्यमी विकास नीति 4.0 (2024-2029) और हथकरघा नीति के दायरे में लाया गया है, जिसके अंतर्गत नीतिगत सहायता सुनिश्चित की गई है। उत्पाद विकास और बाज़ार पहुंच को सुगम बनाने के लिए हितधारकों को वित्तीय सहायता और प्रोत्साहन उपलब्ध कराए गए हैं। एक ओडीओपी प्रकोष्ठ की स्थापना की गई है और साथ ही नामित नोडल अधिकारी और एक व्यापक विक्रेता डेटाबेस भी स्थापित किया गया है, जो सभी सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध हैं। बाजार संबद्धता को मज़बूत करने के लिए राज्य नियमित रूप से सरकारी ई-मार्केटप्लेस (जीईएम) अभियानों और क्रेता-विक्रेता बैठकों के आयोजन के साथ-साथ व्यापार मेलों में सहभागिता सुनिश्चित करता रहा है। हितधारकों के कौशल विकास और शिक्षा जगत, ई-कॉमर्स प्लेटफ़ॉर्म और वित्तीय संस्थानों के साथ साझेदारी को बढ़ावा देने पर भी जोर दिया जा रहा है। इसके अतिरिक्त, ओडीओपी पोर्टल लाइव और पूरी तरह से प्रचालन में है, जो शिकायत निवारण तंत्र के साथ-साथ आवश्यक जानकारियां प्रदान करता है। इसमें प्रत्येक जिले के लिए समर्पित पृष्ठ शामिल है। बाजार में पहुंच को और बढ़ाने के लिए, ओडीओपी उत्पादों को लीपाक्षी और एप्को प्लेटफॉर्म के माध्यम से ऑनलाइन बिक्री के लिए भी उपलब्ध कराया गया है।

आंध्र प्रदेश के लिए चिन्हित (जिलावार) विशिष्ट उत्पादों का विवरण डीपीआईआईटी की वेबसाइट पर निम्नलिखित लिंक पर उपलब्ध है-

https://dpiit.gov.in/sites/default/files/ODOP_Annexure_11August2025.pdf

(ख): आंध्र प्रदेश में कुल निर्यात (मात्रा और मूल्यांकन) के संदर्भ में विशिष्ट जिलावार आंकड़े डीपीआईआईटी के पास उपलब्ध नहीं हैं।

(ग): केंद्रीय बजट 2023-24 में की गई घोषणा के अनुसार, राज्यों को अपनी राजधानियों या प्रमुख पर्यटन केंद्रों में ओडीओपी उत्पादों, भौगोलिक संकेतकों (जीआई) और मेक इन इंडिया पहलों को बढ़ावा देने के लिए पीएम एकता मॉल स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित किया गया था। इसी क्रम में, आंध्र प्रदेश राज्य पीएम एकता मॉल के निर्माण की दिशा में सक्रिय रूप से कार्य कर रहा है। व्यय विभाग की "पूंजी निवेश के लिए राज्यों को विशेष सहायता स्कीम (एसएएससीआई) 2023-24" के तहत इस मॉल के निर्माण और संचालन के लिए 172 करोड़ रुपए का बजट आबंटित किया गया है। इस परियोजना के लिए विशाखापट्टनम में पांच एकड़ के क्षेत्रफल वाले एक स्थल को चिन्हित किया गया है, और हथकरघा एवं वस्त्र विभाग इसके कार्यान्वयन के लिए नोडल विभाग के रूप में नामित है। राज्य द्वारा प्रस्तुत विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) को डीपीआईआईटी द्वारा अनुमोदित किया गया था और **व्यय विभाग द्वारा 30 जनवरी, 2024 को निधि जारी करने का स्वीकृति आदेश जारी किया गया था**। स्थल पर निर्माण गतिविधियां शुरू कर दी गई हैं, जिनके मई 2026 तक पूरा होने की संभावना है।

एकता मॉल के डिज़ाइन में 36 राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के साथ-साथ आंध्र प्रदेश के 26 ज़िलों के लिए समर्पित खुदरा व्यापार हेतु स्थान शामिल हैं। इसमें मनोरंजन और सांस्कृतिक क्षेत्र, सम्मेलन कक्ष, प्रौद्योगिकी-समाहित अनुभव, आवश्यक सुविधाएं, समावेशी स्वरूप की सुविधाएं और आगंतुकों की सहभागिता बढ़ाने के लिए एक फीडबैक तंत्र भी शामिल है।

(घ): ओडीओपी पहल के तहत, ओडीओपी आधारित उत्पादों की बिक्री और विजिबिलिटी बढ़ाने के लिए आंध्र प्रदेश में एमएसएमई, उद्यमियों, कारीगरों, बुनकरों, किसानों और अन्य हितधारकों को प्रशिक्षित करने और सहायता प्रदान करने के लिए कई कदम उठाए गए हैं। एक डिजिटल ओडीओपी उपहार कैटलॉग लॉन्च किया गया है, जिसमें समस्त भारत के 1000 से अधिक उत्पाद शामिल हैं। इनमें आंध्र प्रदेश के एटिकोप्पाका खिलौने और धर्मावरम सिल्क साड़ियां जैसी उल्लेखनीय वस्तुएं शामिल हैं। ओडीओपी उत्पादों को सरकारी ई-मार्केटप्लेस (जीईएम) में शामिल करने के भी प्रयास किए गए हैं, जिसमें वर्तमान में राज्य के 49 उत्पाद सूचीबद्ध हैं, जिनमें हथकरघा, हस्तशिल्प, वस्त्र, समुद्री भोजन, प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ और कृषि उत्पाद शामिल हैं।

क्षमता निर्माण के संदर्भ में, ओडीओपी ने आंध्र प्रदेश के विभिन्न जिलों में डिजाइन जागरूकता कार्यशालाओं की एक श्रृंखला आयोजित करने के लिए राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान (एनआईडी) से सहयोग किया। ये कार्यशालाएं पारंपरिक कारीगरों के बीच डिज़ाइन नवप्रयोग और जागरूकता बढ़ाने पर केंद्रित थीं, जिनमें कलमकारी ब्लॉक

प्रिंटिंग, एटिकोप्पाका और कोंडापल्ली खिलौने, और पेन कलमकारी जैसे शिल्प शामिल थे और इनके सत्र सितंबर 2024 और जनवरी 2025 के बीच आयोजित किए गए थे। इसके अतिरिक्त, आंध्र प्रदेश के ओडीओपी उत्पादों को प्रमुख राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय आयोजनों, जैसे भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला (आईआईटीएफ) 2024, वर्ल्ड फ़ूड इंडिया 2024 और विदेशों में स्थित भारतीय मिशनों के सहयोग से वैश्विक मंचों पर प्रमुखता से प्रदर्शित किया गया है। इसमें कजाकिस्तान में ओडीओपी बिजनेस राउंडटेबल और मालदीव में आयोजित अतुल्य भारत उत्सव शामिल हैं। ये पहलें, युवाओं, महिलाओं और जमीनी स्तर के उत्पादकों पर ध्यान केन्द्रित करते हुए, ओडीओपी उद्यमिता और क्षमता निर्माण को बढ़ावा देने की दिशा में सरकार के निरंतर प्रयासों को दर्शाती हैं।

*****